PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES
RAJASTHAN

दिनांक: 30.12.2016

प्रेस विज्ञप्ति

प्रारम्भिक रपट

नोटबन्दी का दैनिक मजदूरों पर असर
जयपुर शहर के चैकटी मजदूर (श्रम बाजारों)का एक त्वरित आंकलन

55 वर्षीय विजय जी का कहना है, कर्ज लेने पर ब्याज देना पड़ रहा है सो रुपये पर पांच रुपये का ब्याज, 2000 का नोट बदलाने पर 200 रुपए काट कर 1800 रुपये वापिस होतें हैं. रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक ने निकाल दिया। दस दिनों से सड़क पर सोना पड रहा है। बीबी बीमार है तो अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं हैं'। बहन की तै हु ईशादी कैन्सिल करनी पड़ी है।

'मेरी माँ मर गयी साहब वो बहु तबीमार थी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे'' हमें सूखी रोटी नमक से खानी पड़ी।' जामिलान याजू, 50, दादी का फाटक।

30 वर्ष के बाबूलाल का कहना है, "हमे दस दिन भूखा सोना पड़ता है। मालिक ने घर से निकाल दिया, उधारी पे जिंदगी चल रही है, अब तो लोग उधार देने से भी मना कर रहे हैं।

9 नवम्बर, 2016 से देष में 500 और 1000 रूपयों के पुराने नोटों के लेन-देन बन्द कर दिये जाने के बाद से देष में हु यीभारती किल्लत के कारण सबसे अधिक प्रभाव कामगारों पर पड़ा, विषेषकर उन कामगारों पर जो दिन-प्रतिदिन काम की खोज मे बाहर निकलते हैं। जयपुर शहर के इन मजदूरों पर नोटबन्दी का क्या असर हु आइस हेतु हमने एक त्वरित अध्ययन जयपुर की चैकटियों पर दिसम्बर 20-23, 2016 के दौरान किया। कुल 20 चैकटियों के 737 मजदूरों से जानकारी प्राप्त की गयी। देष के विभिन्न 13 विष्व विद्यालयों व विद्यी काॅलेजों के 64 छात्र-छात्राओं ने पांच दलों में बंटकर यह सर्वे किया। यह सर्वे पी.यू.सी.एल. राजस्थान व बी.जी.वी.एस. राजस्थान के सदस्यो के साथ किया गया।

सर्वे कार्य तीन उद्देष्यों को लेकर किया गया। पहला, नोट बन्दी का काम, आय, भोजन और सम्बन्धो पर क्या असर पड़ा यह जानने हेतु। दूसरा कामगारों बैंक-व्यवहार जानने हेतु और तीसरा उनकी नोटबंदी एवं काले धन के बारे में समझ एवं राय जानने हेतु। जानकारी प्रष्नावली के माध्यम से ली गयी।

कुल 737 कामगारों में मात्र 96 महिलाएँ थी। लगभग तीस प्रतिषत कामगार एकेले रहते हैं, प्रवासी मजदूर हैं।

नोटबन्दी का असर

नीचे दी गयी तालिका में नोटबन्दी के असर की व्यापकता एवं गहरायी स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है।

व्यापकता:-

- 94.3 प्रतिषत कामगारों का कहना है कि उनके काम में कमी आयी हैं। यह कमी लगभग 40 प्रतिषत हैं। 57.7 प्रतिषत लोगो को रोजगार मिलता था वो घट कर 35.4 प्रतिषत रह गया।
- 95.39 प्रतिषत कामगारों का कहना है कि उनकी आय नोट बन्दी से कम हो गयी है। औसतम कम से कम दैनिक मजूदरी 450 रूपये से घटकर 264 रूपये रह गई है।
- 85.89 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके खाने पर विपरित असर पड़ा है।
- 26.59 प्रतिषत कामगारों ने कहा कि नोट बन्दी से बच्चों की षिक्षा, बीमारी के इलाज, रहने के लिए उपलब्ध छत, शादियों आदि पर विपरित असर पड़ा है।

असर की गहनता:-

नोटबन्दी का असर व्यापक ही नहीं है बहु तगहरा भी है। कई परिवारों का जीवन तितर-बितर हो गया है। सर्वे के दौरान उत्तर दाताओं के निम्न वक्तव्य असर की गहरायी को स्पष्ट करती है।

- बहु त बुरा हु आऔर खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा (38 वर्षीय रमेष मीणा)।
- कुछ नहीं बस इतना जानते हैं कि इस कारण से हम भूखे मर रहे हैं। (35 वर्षीय गीता)
- मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे है, मैं एक महिने से अपने घर भी नहीं जा पा रहा हूँ।(38 वर्षीय राजू)

अमीरो के लिए नोट बदली और गरीबों के लिए नोटबन्दी

नोटबन्दी पर राय देते हु एअधिकतर कामगारों का कहना था कि (54.6) यह एक गलत कदम है और यह नहीं होना चाहिये। क्योंकि काम की कमि के कारण गरीबों की आय पर अकुंष लगा है, अतः गरीबों के लिए ही यह योजना नोटबन्दी साबित हो रही हैं।

कालेधन के बारे में जानकारी

- 36.4 प्रतिषत उत्तरदाता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे नहीं जानते की काला धन क्या होता है।
- 82.6 प्रतिषत का कहना था कि उन्हें नहीं मालुम कि कालाधन किस प्रकार से बनता है।
- 94.8 प्रतिषत ने कहा कि वे नहीं जानते की कालाधन कहाँ पर रखा जाता है।
- 97 प्रतिषत ने कहा उन्हें नहीं मालुम की देष में काला धन कितना है।
- कुछ उत्तरदाताओं के अनुसार काला धन कुछ करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ तक है।
- मात्र 17.8 प्रतिषत ने कहा कि काला धन वह आय है जो कर-चोरी नकली नोट, रिष्वत और काले धन्धों से कमाई जाती है।

- लगभग 45 प्रतिषत को काले धन के बारे में गलत फहमी/मिथ्या धारणा थी, जिन्होंने कहा कि काला धन वो है जो 500/1000 रूपये के पुराने नोटो में हैं, अमीरों का पैसा है, घरों मे जमा किया गया पैसा हैं।

बैंक व्यवहार

नोट बन्दी के घोषित उद्देष्यों में कैसलैस का अघोषित उद्देष्य कुछ ही समय में सरकार का मुख्य उद्देष्य बन गया। इस संघर्ष में सर्वे में कामगारों के बैंक व्यवहार के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी प्राप्त की गयी।

जानकारीनुसार 35 प्रतिषत मजदूरों ने बताया उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। जिनके पास है उनमें अधिकतर के पास जन-धन, नरेगा, गैस और पैसा आदि से सम्बन्धित खाता है। 456 में से 168 मजदूरों के खाते जयपुर से बाहर के है। कुल खाता धारको में 48.16 प्रतिषत ने कहा वो काम मे नहीं लेते, कभी बैंक नहीं गये। 78.1 प्रतिषत ने कहा वे साल में एक आध बार बैंक में जाते है।

निष्कर्ष

- अधिकांष कामगार नोटबन्दी को हितकारी नहीं मानते और इसके विपरित प्रवाओं के कारण स्वीकार योग्य नहीं मानते।
- अधिकांष मजदूर काले-धन के बारे में नहीं जानते। उनको नहीं मालुम काला धन क्या होता है, कैसे बनता हैं कहाँ रखा जाता है। कई इस गलत फहमी का षिकार हैं कि अमीरों का पैसा काला धन है।
- काले धन की गलत समझ के कारण भ्रान्ति मे है कि नोटबन्दी से उनके खातो में सरकार पैसे जमा करायेगी, गरीबी समाप्त हो जायेगी, किसानों का ऋण माफ होगा।
- काम और आय पर व्यापक और गहरा असर हुआहैं। काम की उपलब्धी 60 प्रतिषत से घटकर एक-तिहाई हो गयी है। मजदूरी दर में तेजी गिरावट आयी हैं। आय अन्य सम्बन्धित कारणों से ज्यादा गिरि है। नोटबन्दी के बाद औसत दैनिक मजदूरी 50 से 70 प्रतिषत तक गिरी है।
- कई कामगारों के जीवन पर गंभीर आघात हुआहै। जिन्दगी तितर-बितर हो गयी है। विषेषकर उन पर जो गरीबी की कगार पर खड़े थे। कई परिवार, मजदूर भूख से बेहाल है, बेघर हो गये हैं। बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे, बच्चों का स्कूल छूट रहा है, गहने बेचने का मजबूर है, घरों की शांति भंग हो रही है।
- अधिकांष मजदूर बैंको से सरोकार नहीं रखते। एक तिहाई के पास बैंक खाता नहीं है। जिनके पास है उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभ लेने और जन-धन/भामाषाह योजना के तहत खुलवाये हैं। एक-तिहाई से अधिक कामगारों के खाते जयपुर से बाहर हैं। 56 प्रतिषत खाताधारी बैंक नहीं जाते या साल में एक आध पर जाते हैं। नोटबन्दी के कारण कई कामदारांे ने बैंक जाना बन्द कर दिया आय में कमी के कारण।

मांगें

- राजस्थान के चैकटी वाले सभी को एक साल के लिए दैनिक मजदूरों को सस्ता अनाज, दाले और तेल उपलब्ध कराया जाय।
- श्रम विभाग को तुरन्त प्रभाव से राज्य स्तर पर सभी असंगठित मजदूरों का विषेषकर दैनिक मजदूरों, निर्माण-मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के छोटे-छोटे घरेलू एवं अन्य उद्योगों के मजदूरो का सर्वे करना चाहिये।
- सभी शहरी मजदूरों को अस्थायी-स्थायी घर उपलब्ध करवाना चाहिये। नोट बन्दी से प्रभावित मजदूरों को ''सबको घर'' योजना का लाभ तुरन्त दिया जाना चाहिए।
- सभी प्रभावित मजदूरों की जिनमे बीमार और मृतक शामिल हैं को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिये।
- तुरन्त प्रभाव से ''राजस्थान शहरी मजदूर रोजगार गारण्टी स्कीम'' प्रारम्भ की जानी चाहिये। इस में कार्यरत मजदूरों को केन्द्र द्वारा हाल ही में निष्चित की गयी दैनिक मजदूरी दर से भुगतान होना चाहिये।
- सभी मजदूरो को सामाजिक सुरक्षा कार्ड दिया जाना चाहिये और उन्हें कानूनत सभी सामाजिक सुरक्षा सरकारी कामगारों के समुदाय सुनिष्चित की जानी चाहिये।
- कैषलेस व्यवस्था को थोपा जाना नही चाहिये।